Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to regularize the contractual Group C and D employees in Government Sector.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति जी, देश में सिर्फ तीन परसेंट सरकारी नौकरियां हैं । मेरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जहां देश की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा रहता है, वहां तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी की नौकरियों को भी पूरी तरह से आउट सोर्स कर दिया गया है, जिनमें आरक्षण भी लागू नहीं होता है और उसके साथ-साथ जो वेजेज मिलते हैं, वे सातवें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं मिलते हैं । इस वजह से देश में समानता की जो एक पहल बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी, उस पर कहीं न कहीं एक भारी ठेस पहुंचने का काम हो रहा है । हमारे देश के तमाम गरीब लोगों को अपने जीवन स्तर में बढ़ावा करने में मदद नहीं मिल पा रही है । यह देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गरीबों के साथ बिलकुल खड़ी नहीं है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं और जिन सभी नौकरियों को आउट सोर्स किया जा रहा है, उन्हें रेग्यूलराइज किया जाए, ताकि उन्हें सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेमेंट मिले और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होने का काम हो ।

माननीय सभापति: श्री अरविंद सावंत – उपस्थित नहीं ।

श्री मनीष तिवारी – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ।